कोरोना का खतरा टला नहीं

जब अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी राजनीति को लेकर जिम्मेदार राजनीतिक दल इस तरह का आचरण करेंगे तो सामान्य लोगों से कैसे यह उम्मीद की जाए कि वे संयम बनाए रखें और कहीं भीड़ न लगाएं?

मनोज सिंह।।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने एक बार फिर सबको आगाह किया है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है और उसे लेकर सावधानी में किसी तरह की कमी नहीं आने देनी चाहिए। उसने कहा कि अव्वल तो किसी भी तरह का सामूहिक जुटान होने ही नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर यह अनिवार्य हो तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को शामिल होना चाहिए, जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इस ताजा दिशानिर्देश की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है।

ऐसा बार–बार देखने में आया है कि सरकार की ओर से सख्ती में जरा सी छूट मिलते ही सड़कों पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ने लगती हैं। चाहे पार्कों या बाजारों में पहुंचने वालों की भीड़ हो या पहाड़ों पर उमड़ने वाला सैलानियों का सैलाब। वैसे बात सामान्य लोगों की ही नहीं है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी अपने आचरण से कोई मिसाल नहीं पेश कर पा रहे। महाराष्ट्र कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में था। अभी भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से संयम बरतने और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी निष्ठा से पालन करने की अपील करते रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक केंद्रीय मंत्री के अप्रिय बयान के बाद उनकी पार्टी के लोग ही सड़कों पर निकल आए।

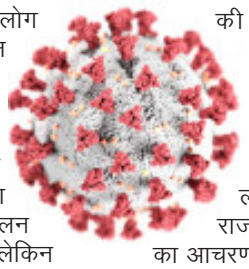

मुख्यमंत्री और शिवसेना नेतृत्व ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। यही स्थिति दूसरी तरफ भी है। पिछले दिनों बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में मंदिर खुलवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे नजर आए। उधर, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस सार्वजनिक रूप से दही हांडी मनाने पर अड़ी हुई थी। जब अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपनी राजनीति को लेकर जिम्मेदार राजनीतिक दल इस तरह का आचरण करेंगे तो सामान्य लोगों से कैसे यह उम्मीद की जाए कि वे संयम बनाए रखें और कहीं भीड़ न लगाएं? बहरहाल, हम सबको यह समझना ही होगा कि खतरा किसी एक को नहीं सबको है। इस बीच टीकाकरण के अभियान में तेजी जरूर आई है, जो एक अच्छी बात है। अगस्त में पूरे महीने का दैनिक टीका औसत 59.29 लाख रहा, जो जुलाई के दैनिक औसत (43.41 लाख) से 36.5 फीसदी ज्यादा है। यही नहीं, अगस्त के आखिरी सप्ताह में तो दैनिक औसत 80 लाख डोज से भी ऊपर रहा। आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद की जा रही है। बावजूद इसके, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा टीकाकरण के सुरक्षा घेरे से बाहर है। नए म्यूटेंट्स का खतरा अलग है। इकॉनमी दूसरी लहर का झटका झेलने के बाद बड़ी मुश्किल से संभलती दिख रही है। ऐसे में तीसरी लहर के बेकाबू होने का जोखिम कतई मोल नहीं लिया जा सकता। जरूरी है कि हम सब इस बात को समझें और सतर्कता में कोई कमी न आने दें।

मूर्खतापूर्ण स्वर

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

वह बैलों को कुछ सलाह देना चाहता था, जिससे इनका कुछ भला हो। एक दिन दोनों बैल खेत जोत रहे थे। बकरा भी वहीं खेतों के पास घास चर रहा था। दोनों बैलों को खेत जोतने में काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वे दोनों हांफ रहे थे। यह देखकर बकरा मूर्खतापूर्ण स्वर में बोला– "भाइयो, तुम दोनों को दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है। परंतु किया क्या जा सकता है, यह तो भाग्य का खेल है। मुझे देखो, मेरे पास दिन भर चरने के अलावा कोई काम नहीं है। दिन भर मैं इधर–उधर मैदानों में चरता रहता हूं। किसान की पत्नी खुद खेतों में जाती है और मेरे लिए हरी पत्तियां और घास लेकर आती है। तुम दोनों तो मुझसे ईर्ष्या करते होगे।"

संपादकीय

सामरिक पहलू

मुद्दा भले ही कृषि कानूनों से जुड़ा है, लेकिन अगर आपसी अविश्वास की खाई चौड़ी हुई, तो देश विरोधी तत्व उसका फायदा उठाने में चूकेंगे नहीं। इस बात को समझने के लिए किसी गुणा–भाग की जरूरत नहीं है। इतिहास और इंसानी व्यवहार की समझ रखने वाला कोई भी आम नागरिक इस बात को आसानी से समझ सकता है। हम इस बात को जितनी जल्दी समझ लें, उतना ही अच्छा है। नहीं तो, हम सभी का नुकसान होगा। कृषि प्रधान भारत में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा 'जय जवान, जय किसान' आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। इस तथ्य को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि अधिकतर जवान कृषक वर्ग से ही आते हैं। अभी तक हमने कृषि का आर्थिक और खाद्य सुरक्षा का पहलू ही देखा है, लेकिन मौजूदा हालात में इसका सामरिक सुरक्षा से जुड़ा पहलू भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पर लखीमपुर हिंसा और न्यायिक कार्यवाही जैसे मसले आग में घी का काम करते हैं। इसलिए सभी जिम्मेदार लोगों को आगे आकर इस समस्या का जल्दी समाधान निकालना चाहिए, ताकि एक सामान्य आंदोलन देश की सुरक्षा के लिए खतरा न बन जाए।

कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में बदलाव समय की मांग है। अब खेती में तकनीक के इस्तेमाल और भूमि सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। खेती से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारना होगा।

खेती में सुधार जरूरी

आनंद प्रकाश माहेश्वरी।।

केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों पर काफी बहस हो चुकी है। इससे कई सवाल भी उपजे हैं। मसलन, क्या छोटे और सीमांत किसान ताकतवर कॉरपोरेट जगत के सामने मजबूती से अपनी शर्तें रख सकेंगे? क्या कम पढ़े–लिखे किसान डिजिटल माध्यमों का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे? इसी तरह की कई और उलझनें भी हैं। हालांकि, नए कृषि कानूनों के पक्ष में भी कई दलीलें दी गई हैं। इनमें खासतौर पर किसानों को शोषण से बचाने वाले मसले पर ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे कि किसी भी हालात में कॉरपोरेट वर्ल्ड निवेश की आड़ में किसानों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकता। दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का खास ख्याल रखा जाएगा। इसके बावजूद किसान संगठन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ऐसी अटकलें भी हैं कि नए कानूनों के लागू होने पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) का प्रावधान खत्म हो जाएगा। कुछ इलाकों में बड़े किसानों की आमदनी घटने की आशंका जताई जा रही है और नए कानूनों को वापस लेने का सबसे ज्यादा दबाव भी वही बना रहे हैं।

यह भी एक अहम पहलू है कि भारत की जीडीपी का तकरीबन 17 फीसदी हिस्सा कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों से आता है। यह देश

के लगभग 42 फीसदी लोगों को रोजगार भी देता है। लेकिन आज भी ज्यादातर हिस्सों में खेती परंपरागत तरीके से ही होती है। इससे जोखिम की आशंका बराबर बनी रहती है। कहने का मतलब है कि कृषि क्षेत्र में बदलाव समय की मांग है। अब खेती में तकनीक के इस्तेमाल और भूमि सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। फसल की बुआई बाजार में मांग के हिसाब से होनी चाहिए। खेती से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारना होगा। किसानों को फसल बेचने के लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट और भंडारण के लिए अच्छी सुविधाएं देनी होंगी। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही नुकसान का जोखिम भी कम होगा।

बहरहाल, नए कृषि कानूनों से उभरे असंतोष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे आखिर में नुकसान देश का ही होगा। यह भी समझने वाली बात है कि अगर आपको ठोस बदलाव लाना है, तो पहले उससे जुड़े सभी पक्षों का भरोसा जीतना पड़ता है। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है, अनचाही मुसीबतों को दावत देना। फिर बात इतनी भी बिगड़ सकती है कि इसका फायदा देश विरोधी ताकतें भी उठा लेंगी। इस वक्त कई बाहरी ताकतें छद्म युद्ध के जरिए देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश भी कर रही हैं। ऐसे में किसी भी असंतोष को लंबा खींचकर हम देश का बुरा चाहने वालों का काम आसान कर रहे हैं। इसका फायदा उठाने के लिए कई तरह स्लीपर सेल सक्रिय हो जाएंगे।

गड़े मुर्दों को उखाड़कर उन पर सियासत होने लगेगी। भड़काऊ बयानबाजी से नफरत और हिंसा का माहौल बनाया जाने लगेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये सारे डर निराधार हैं। अतीत में जमीन और किसानों से जुड़े कई आंदोलनों का सही तरीके से समाधान नहीं निकाला गया। लिहाजा, देश में नक्सली तत्व पनप गए और वह समस्या जस की तस है। आतंकी संगठन भी इसका फायदा उठाते हैं और गरीब या फिर कम पढ़े–लिखे लोगों को बहला–फुसलाकर अपने साथ मिला लेते हैं। नौजवानों को सब्जबाग दिखाकर उनकी जड़ें मुख्यधारा से काट देते हैं। यहीं से हमारी असल चिंता पैदा होती है और एक सामान्य सा दिखने वाला आंदोलन सामरिक नजरिए से महत्वपूर्ण हो जाता है।

सूडोकु नवताल-5272

4					1	9		
						8	5	
			7	3				
			3				4	7
9								2
8	5				6			
				5	8			
	7	4						
		6	2					5

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5271 का हल

2	4	5	6	9	8	1	7	3
1	7	6	4	3	5	8	2	9
3	8	9	1	2	7	6	5	4
9	1	7	3	6	2	4	8	5
5	6	3	8	7	4	9	1	2
4	2	8	5	1	9	3	6	7
7	3	1	9	5	6	2	4	8
8	9	2	7	4	1	5	3	6
6	5	4	2	8	3	7	9	1

अपना ब्लॉग

सोशल मीडिया का सहारा

मोहन। कई मामलों में सोशल मीडिया का सहारा लेकर भी लोगों को फंसाया जाता है। उन्हें बरगलाकर गलत काम करने के लिए उकसाया जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि गलत काम उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, लेकिन आतंकी घटनाओं की जांच से पता चला है कि अधिकतर मामलों में बाहरी ताकतों का हाथ होता है। वे लोग स्थानीय लोगों को मोहरा बस इसलिए बनाते हैं, ताकि उस मामले में अपना हाथ होने की बात नकार सकें। एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व युद्ध में 37 में से सिर्फ 9 देशों की बाहरी हमले की वजह से हार हुई। बाकी सभी देश अपनी कमजोर आंतरिक सुरक्षा के चलते पस्त हुए। छद्म युद्ध जैसे हालात में हरेक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हर नागरिक बिना वर्दी का सिपाही होता है। इसी तरह हर सिपाही वर्दी में एक नागरिक होता है। इसलिए देश की भलाई के लिए आपसी अविश्वास और असंतोष की खाई को पाटकर मिलजुल काम करना होगा।